

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 1981/27 चैत्र, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(अनुभाग-सी)

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अप्रैल, 1981

सं० सा० प्र० वि० (पी० ए०)-4 (घ)-49/78-ग-खण्ड-II.—हिमाचल प्रदेश
के राज्यपाल महोदय इस बारे में जारी की गई पूर्वगामी सभी अधिसूचनाओं का

अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 7-क के अधीन उन में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमों को सहर्ष बनाते ह :-

संक्षिप्त नाम 1. (1) ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के (भवन निर्माण तथा प्रारम्भ। हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 कहलाएंगे।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. इन नियमों में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम 4) से है ;

(ख) "सम्मोदक प्राधिकारी" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ग) "अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश के विधान के यथा स्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष से है ; तथा

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द तथा पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अग्रिम राशि कब स्वीकार्य है।

3. यथा स्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के (मोटरकार के लिये अग्रिम धनराशि) नियम, 1971 के अधीन अग्रिम राशि की सुविधा का लाभ न उठाया हो, के द्वारा प्रारूप-1 पर दिये गये आवेदन पर उनके समुचित जीवन स्तर का ध्यान रखते हुए अपना भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन को खरीदने के लिये प्रतिदेय अग्रिम धन राशि दी जा सकती है।

अधिकतम अग्रिम राशि।

4. यथा स्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन को खरीदने के लिये अधिक से अधिक साठ हजार रुपये अथवा भवन के वास्तविक मूल्य अथवा उसके निर्माण की कुल लागत, जो भी कम हो, को अग्रिम धन राशि दी जा सकती है।

भुगतान की प्रणाली।

5. इन नियमों के अधीन अग्रिम धन राशि का भुगतान निम्नलिखित ढंग से किया जायगा :-

(1) अपने भवन के निर्माण के लिए :

(क) पहली किस्त—निर्माण आरम्भ करने के लिए—स्वीकृत धन राशि के 50 प्रतिशत के बराबर।

(ख) दूसरी तथा अन्तिम किस्त—जब भवन छत की सतह तक पूर्ण हो जाये—स्वीकृत कुल अग्रिम धन राशि का शेष 50 प्रतिशत।

(2) नव निर्मित भवन को खरीदने के लिए—एकमुश्त राशि।

टिप्पणी.—अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त की गई धन राशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह धन राशि उन्हें अग्रिम धन के रूप में दी गई थी, यह प्रमाण पत्र उन द्वारा राशि के उक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा।

6. (1) नियम 4 के अधीन स्वीकृत अग्रिम धन राशि तथा उस पर प्रोद्भूत व्याज की वसूली 120 समान मासिक किस्तों में की जायेगी। सरकार शेष कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि स्वयं ऐसा चाहें तो कम किस्तों में वसूली का आदेश दे सकती है। कटौती प्रथम किस्त/या एकमुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् लिए जाने वाले वेतन से आरम्भ की जायेगी।

अग्रिम धन राशि की वसूली।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली उसी प्रकार की अग्रिम राशि पर समय-समय पर नियत किये जाने वाले व्याज दर के अनुसार इस राशि पर साधारण व्याज लिया जायेगा परन्तु अग्रिम राशि लेने के समय नियत की गई व्याज दर अग्रिम राशि के पूरे समय तक वही बनी रहेगी।

(3) यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर नहीं बना रहता परन्तु विधान सभा सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में मिलने वाले विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जायेगी।

(4) यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व किसी कारणवश विधान सभा सदस्य के पद पर भी नहीं बना रहता परन्तु पेंशन का हकदार होता है तो उसे मिलने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जायेगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से खजाने में जमा की जायेगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पेंशन का हकदार भी नहीं बनता तो उसे मासिक किस्तें उस पर प्रोद्भूत व्याज सहित नियमित रूप से प्रतिमास सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी तथा इसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रेषित करनी पड़ेगी।

(6) अग्रिम धन राशि तथा उस पर प्रोद्भूत व्याज की वसूली से पूर्व ही मृत्यु की दशा में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा विधान सभा सदस्य के वैधिक उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) द्वारा मासिक किस्त नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा कराई जायेगी जिसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को हर मास प्रेषित करनी होगी।

(7) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनका वैधिक प्रतिनिधि, यथास्थिति, अग्रिम धन राशि अथवा उस पर व्याज की मासिक किस्त की नियमित अदायगी नहीं करता या यदि वह दिवालिया हो जाता है या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल राशि या उस में से इतना जितना कि उस समय देय तथा असंदत रहा हो, सरकार को उस पर विहित दर से व्याज सहित एकमुश्त में तत्काल देय होगा। सरकार को उपरोक्त बकाया राशि को "भू-राजस्व के बकाया" के रूप में वसूल करने को छूट होगी।

व्याख्या.—मासिक रूप में वसूल की जाने वाली अग्रिम धन राशि अन्तिम किस्त जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है को छोड़ कर पूरे रुपये में नियत की जायेगी।

ऋण के भुगतान की सुरक्षा हेतु बंधक पत्र निष्पादन का उत्तरदायित्व।

7. यथास्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, का यदि अग्रिम धन तथा उस पर संभूत ब्याज के पूर्ण परिशोधन होने से पूर्व ही निधन हो जाता है अथवा वह अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं रहता है तो उसके फलस्वरूप सरकार को होने वाली हानि से प्रतिभूत करने हेतु उस भवन को जो कि निर्मित किया गया है अथवा खरीदा गया है को उस भूमि सहित जिस पर वह भवन है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप-II पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बंधक किया जायेगा जिसका निष्पादन पहली किस्त अथवा एकमुश्त राशि के भुगतान से पूर्व, यथास्थिति, किया जायेगा तथा देय राशि की पूरी अदायगी के पश्चात बंधक को इन नियमों में संलग्न प्रारूप-III पर प्रतिहस्तांतरण विलेख के निष्पादन पर मुक्त किया जायेगा। बंधक पत्र के निष्पादन होने पर, सम्मोदक प्राधिकारी, उस भूमि पर, जिस पर उक्त भवन खड़ा है या उसे निर्मित करने का प्रस्ताव है, आवेदक के हक की शुद्धता से अपने आप को सन्तुष्ट करेगा।

परिसर को अच्छी अवस्था में रखने तथा प्राग के जोखिम आदि के लिये बीमा कराने का दायित्व।

8. अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने खर्च पर भवन को अच्छी अवस्था में रखेंगे तथा इसे सभी ऋण भारों से भी मुक्त रखेंगे। वह इस को आग, बाढ़ आदि-आदि के लिये इतनी राशि तक बीमा करवाएँगे जो कि स्वीकृत अग्रिम धन राशि से कम न हो, तथा इस प्रयोजन का वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

अग्रिम जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व दिया गया है।

9. इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दिया गया गृह-निर्माण अग्रिम ऋण इन नियमों के अधीन दिया गया समझा जायेगा तथा इन नियमों के सभी उपबन्ध ऐसे किसी अग्रिम तथा इसकी वसूली पर लागू होंगे।

प्रारूप-I

(नियम 3 देखिये)

भवन निर्माण हेतु अग्रिम धन राशि के लिये आवेदन का प्रारूप

1. विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का नाम स्पष्ट अक्षरों में
2. अपेक्षित अग्रिम की धन राशि, निर्दिष्ट करते हुये आया कि :
 (i) भवन निर्माण के लिये अपेक्षित, अथवा
 (ii) बने हुये भवन के लिये अपेक्षित

3. उस स्थान, जहाँ पर भवन बनाया जाना है, यह उल्लेख करते हुये आया कि वह किसी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आता है का ब्योरा। यदि वह स्थानीय निकाय की सीमा में है, तो सम्बन्धित निकाय के नक्शा

स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति संलग्न की जाए। प्रस्तावित भवन के विस्तृत नक्शे जिसमें किसी अधिकारी जो कि सहायक इंजीनियर के स्तर से निम्न का न हो द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कुल खर्च का अनुमान दिया गया हो तथा यदि ऋण बने हुये भवन की खरीद के लिये अपेक्षित हो, तो भवन की लागत के उचित होने के सम्बन्ध में वास्तुविद्वद् अर्थात् आर्किटेक्ट का प्रमाण-पत्र, साथ लगाया जाय।

4. किस्तों की संख्या, अग्रिम धनराशि ली जानी प्रस्तावित है अथवा एकमुश्त में.....
5. ऋण वापसी के लिये प्रस्तावित किस्तों की संख्या.....
6. आयाकि वह प्लॉट जिस पर विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष भवन निर्माण का इरादा रखते हैं उनके स्वामित्व और कब्जे में है.....
7. प्लॉट/जमीन, जिस पर आवेदक भवन निर्माण का इरादा रखता है, पर उसके हक का प्रमाणित सबूत.....
8. समय जिसके अन्दर विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ करेगा, और उसके मुकम्मल होने की अवधि.....

प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं बने हुए भवन/प्लॉट जिस पर भवन बनाया जाना है, को बन्धक रखूंगा तथा बन्धक-पत्र निष्पादित और पंजीकृत करवाऊंगा।

प्रमाणित करता हूँ कि मैंने हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (मोटरकार के लिये अग्रिम धनराशि) नियम, 1971 के अधीन मोटरकार खरीदने के लिये ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं की है।

(विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

1. दिनांक.....
2. संलग्न.....

प्रारूप-II

(नियम 7 देखिये)

भवन-निर्माण अग्रिम धनराशि के लिये बन्धक का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री जो कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष है (जिन्हें इसमें आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, यहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके वारिस, निष्पादक और समनुदेशिनी भी है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय (जिन्हें इसमें आगे "बन्धक ग्राहीता" कहा गया है और इस के अन्तर्गत, यहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी है) आज तारीख..... को किया गया है।

चूंकि एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तांतरित और परोपित की जाने वाली भूमि-दाये और परिसरों जिन्हें इसमें आगे वर्णित और अभिव्यक्त किया गया है (इसमें इसके पश्चात् "उक्तदाय" कहा गया है) पर बन्धक-कर्ता का निरंकुश रूप में अभिग्रहण और कब्जा है अथवा अन्यथा रूप में उनका यह हकदार सही है;

और चूंकि बन्धककर्ता ने बन्धक ग्राहीता को अपने निजी प्रयोग के लिये अपना भवन बनाने के लिये/नव निर्मित भवन खरीदने हेतु रुपये को अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन पत्र दिया है ;

और चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिये अग्रिम ऋण) नियम, 1981 (जिन्हें इस में इसके आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इनके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के अनुकूल है, वर्तमान प्रवृत्त नियम, उनका कोई संशोधन या उस में कोई वर्धन भी आता है) बन्धक ग्राहीता ने बन्धककर्ता को रुपये की उक्त रकम निम्नलिखित रूप में भुगतान योग्य अग्रिम धनराशि के रूप में देने को सहमत है :

- (क) निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए रुपये
- (ख) भवन को छत की सतह तक पूर्ण कर लेने के पश्चात् रुपये
- (ग) अथवा एकमुश्त राशि के रूप में रुपये

यह करार इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त करार के अनुसरण में तथा बन्धक ग्राहीता द्वारा बन्धक कर्ता को इसमें इस से पूर्व उल्लिखित खर्चों को करने में बन्धककर्ता को योग्य बनाने के प्रयोजन से इस करार के निष्पादन के पश्चात् या उस से पहले प्रदत्त रुपये (रुपये)
(जिसको पावती बन्धककर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) (और ऐसी और धनराशि जो इस करार में आगे उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में बन्धकग्राहीता द्वारा बन्धक कर्ता को दी जायेगी) और उस पर उक्त नियमों में निर्धारित रीति से गणित व्याज जिसकी पुनः अदायगी के लिए बन्धककर्ता एतद्द्वारा संश्रावित करता है के प्रतिफल के लिए बन्धककर्ता यह करार करता है ;

और यह करार इस बात का भी साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए बन्धकर्ता बन्धकग्राहीता को इस सारे भूखण्ड को जो बन्धककर्ता के लगभग कब्जे में है तथा जो जिले पंजीकरण जिला के में स्थित है तथा उप-पंजीकरण जिला के के पूर्व में से दक्षिण में से तथा पश्चिम में से परिसीमित है एवं उस पर अब बनाये गये रिहायशी मकान अथवा इसके पश्चात् बनाये जाने वाले रिहायशी मकानों के साथ उक्त दाय के सभी अधिकार, सुखाधिकार, अनुलग्न और उक्त भूमि के खण्ड पर इसके पश्चात् खड़े किये गये या बनाये गये मकानों को बन्धक ग्राहीता के और उसकी ओर से पूर्ण प्रयोग के लिये इस में इसके पश्चात् निहित परन्तुक में दिये गये विमोचन के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुये एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तान्तरित और प्रगोपित करता है।

संवन्धा यह भी करार किया जाता है कि यदि और ज्यों ही इस करार में उल्लिखित प्रतिभूति पर की गई उक्त अग्रिम धनराशि रुपये (और ऐसी अन्य रकम जिनका यथा पूर्वोक्त भुगतान किया गया हो) और उक्त नियमों में उपबन्धित या किसी अन्य रीति से गणित उस पर व्याज आदि वापिस किया जाता है, तब और ऐसी स्थिति में बन्धकग्राही बन्धककर्ता की प्रार्थना और लागत पर बन्धककर्ता के प्रयोग और उसकी ओर से प्रयोग अथवा जैसे वह निर्देश दे, उक्त दायों को पुनः स्वत्वान्तरित, पुनः हस्तांतरित और पुनः प्रगोपित करेगा और इस द्वारा यह करार अथवा घोषित किया जाता है कि यदि बन्धककर्ता इकरार को भंग करता है और यदि उक्त रकम रुपये (और कोई अन्य रकम जिसका यथा पूर्व भुगतान किया जाना हो) और उक्त नियमों के अनुसार उस पर गणित किये गये व्याज के पूरे भुगतान से पहले यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या वे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहते हैं तो इस प्रकार की सभी स्थितियों में बन्धकग्राहीता के लिये विधि मान्य होगा कि वह उक्त दाय को या उसके किसी अंश को इकट्ठे या आंशिक रूप से सार्वजनिक या निजी संविदा के द्वारा, संविदा को रद्द या निरस्त करने की शक्ति सहित विक्रय और उस द्वारा होने वाली हानि के लिये उत्तरदायी हुये/पुनः विक्रय

कर सके तथा वह ऐसे किसी विक्रय, जिसे बन्धकग्राही उपयुक्त समझे, को करने और उस के लिये आवश्यक सभी कार्यों तथा आश्वासनों को निष्पन्न करने में सक्षम होगा तथा एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि बन्धकग्राहिता विक्रीत परिसरों तथा उसके किसी भाग से प्राप्त विक्रय आगम में से क्रेता अथवा क्रेताओं को अचूक रूप से मुक्त करेगा, तथा एतद्वारा घोषित किया जाता है कि बन्धकग्राहिता पूर्वोक्त शक्ति के अनुसरण में किये गये विक्रय से प्राप्त धनराशि को न्यास के रूप में रखेगा, उस में से सर्व प्रथम ऐसे विक्रय पर उपगत हुये खर्च का भुगतान करेगा, उसके पश्चात् इस करार की प्रतिभूति पर फिलहाल देय रकमों के भुगतान की और उस धनराशि से रकम लगायगा और तब शेष (यदि कोई हो) बन्धककर्ता को देगा तथा एतद्वारा यह माना जाता है तथा घोषित किया जाता है कि उक्त नियमों को इस करार का अंग समझा और माना जायेगा।

बन्धककर्ता, बन्धकग्राहिता के साथ एतद्वारा यह संधावित करता है कि वह बन्धककर्ता अपनी अनुभूति के चालू रहन के दौरान, इस करार और उक्तदाय के सम्बन्ध से पालित और अनुष्ठित किये जाने वाले उक्त नियमों के उपबन्धों और शर्तों का पालन और अनुष्ठान करेगा।

इसके फलस्वरूप बन्धककर्ता ने इस विलेख पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त बन्धकदाता के द्वारा हस्ताक्षरित:—

(1) पहला साक्षी

पता

पेशा

(2) दूसरा साक्षी

पता

पेशा

प्रारूप-III

(नियम-7 देखिये)

भवन निर्माण अभिगमों हेतु हस्तान्तरण-पत्र

यह अनुबन्ध विलेख दिनांक..... 198 को एक पक्षकार के रूप में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके आगे "सरकार" कहा गया है) एक पक्ष और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री..... अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (जिन्हें इसके आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है) के बीच किया गया, वह उस बन्धक-पत्र के अनुबन्ध-विलेख का अनुपूरक है जो कि दिनांक..... 198 को एक पक्षकार के रूप में बन्धककर्ता तथा दूसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के बीच किया गया था तथा जो पुस्तिका के खण्ड..... पृष्ठ..... से..... पर क्रम में पंजीकृत है। (जिसे इसके आगे "मुख्य अनुबन्ध विलेख" कहा गया है)।

चूंकि मुख्य अनुबन्ध विलेख के अधीन देय राशि अदा कर दी गई है और उक्त विलेख की प्रतिभूति का दायित्व पूर्णतया शोधित है तथा राज्यपाल बन्धककर्ता के निवेदन पर लिखित अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट प्रति, हस्तान्तरण, जैसा कि एतदुपरान्त समाविष्ट है के निष्पादन के लिये सहमत हो गये हैं।

अब यह अनुबन्ध-विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त मुख्य विलेख के अनुसरण में और वचनों के प्रतिफल में राज्यपाल एतद्वारा बन्धककर्त्ता, उसके वारिस, निष्पादक तथा समनुदेशाती को भूमि के उन सभी भागों जो.....में स्थित है, व उत्तर में.....से दक्षिण में.....से पूर्व में.....से तथा पश्चिम में लगभग..... तक परिसीमित है तथा जिस में उन परिसरों से अन्यथा सामुहिक रूप से उस पर बने निवास स्थान, बाह्य कार्यालय, अश्वशाला, पाकशाला आदि सम्मिलित है तथा जो मुख्य अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट या जिनका एतद्वारा प्रगोषित होना अभिव्यक्त है अथवा जो कि अब मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण अथवा इसके विमोचन के अध्याधीन किसी भी प्रकार राज्यपाल में निहित उनके अधिकारों, सुविधाओं तथा अनुलग्नकों जैसा कि मुख्य अनुबन्ध विलेख में अभिव्यक्त है तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण उसी परिसर में से अथवा पर राज्यपाल के सभी सफदा अधिकार, स्वत्वधिकार, हित, सम्पत्ति, प्रभार तथा मांगें जो भी कोई हो तथा उन परिसरों जो एतद्वारा इससे पूर्व बन्धककर्त्ता, उसके वारिसों, निष्पादक, प्रबन्धक तथा समनुदेशितों में तथा उसके प्रयोग के लिये स्वीकृत, नियत तथा प्रतिहस्तान्तरित है को रखन अथवा बनाये रखने के लिये तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख द्वारा रक्षित होने के लिये उस सारे धन से अथवा उपरोक्त राशि अथवा उसके किसी भी अंश अथवा परिसर व मुख्य अनुबन्ध-विलेख से सम्बद्ध सभी कार्यों, वादों, लेखों, दावों, मांगों से सदा के लिये मुक्त करता है, तथा राज्यपाल एतद्वारा बन्धककर्त्ता, उसके वारिसों, समनुदेशितों तथा प्रबन्धकों के साथ इसे व्यवहृत करते हैं तथा अभिहस्तांकित करते हैं कि राज्यपाल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है अथवा इसके लिये जानबूझ कर समनुज्ञा नहीं की है अथवा इसके लिये वह एक पक्ष अथवा सहभागी नहीं रहे हैं जिसके द्वारा उपरोक्त परिसर अथवा उसके किसी भी भाग के लिए उन पर महाभियोग लाया जाए या लाया जा सकता है या स्वत्वधिकार, सम्पदा अथवा इसके अन्यथा जो भी हो में परिवन्धन अथवा रुकावट लाई जा सके। इसके साक्ष्य स्वरूप इस से सम्बद्ध पक्षकारों ने इस पर उपरलिखित दिन और वर्ष को मोहर सहित अपने हस्ताक्षर किये हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से.....
के सम्मुख हस्ताक्षरित, मोहर बन्द तथा प्रदत्त ।

[Authoritative English text under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of loan for House Building) Rules, 1981, notified vide Notification No. GAD (PA) 4 (D) 49/78-C, Vol. II, dated 2nd April. 1981].

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) "Act" means the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971);
- (b) "sanctioning authority" means the Governor of Himachal Pradesh;
- (c) "The Speaker" or "the Deputy Speaker" means the Speaker or the Deputy Speaker as the case may be of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;
- (d) all other terms and expressions used in these rules, but not defined, herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Advance when admissible.*—On an application made in Form I, by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be who has not availed himself of the facility of an advance under the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971, may be paid a repayable advance, for the construction of his own house or for the purchase of a built-up house, with a view to have a reasonable standard of living.

4. *Maximum amount of advance.*—The maximum amount which may be advanced to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be for the construction of a house or for the purchase of a built-up house shall not exceed sixty thousand rupees or the actual price or cost of the construction of house, whichever be less.

5. *Mode of payment.*—The amount of advance admissible under these rules shall be paid in the following manner:—

(1) for the construction of his own house—

- (a) first instalment equal to 50% of the advance sanctioned, for starting the construction;
- (b) second and final instalment of the remaining 50% of the total advance, after the house has been completed upto the roofs level.

(2) for the purchase of the new built-up house in lump-sum.

Note.—A certificate which must be furnished by the Speaker/Deputy Speaker certifying that the amount drawn has been utilised by him for the purpose for which it was advanced to him will be sufficient proof of the amount having been actually utilised by him for the aforesaid purpose.

6. *Recovery of Advances.*—(1) Recovery of the advance granted under rule 4 together with interest thereon, shall be made in 120 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a small number of instalments keeping in view the remaining period of term of office or if the Speaker/Deputy Speaker himself so desires. The deduction shall commence with the first issue of salary after the first instalment of/or lump sum advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate fixed by the Himachal Pradesh Government from time to time for similar advances sanctioned to its Government servants shall be charged; provided, however, that the rate fixed when the advance is sanctioned shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, ceases to be a Speaker/Deputy Speaker for any reason, before the advance is fully repaid, but continues to be the Member of Legislative Assembly, the monthly instalments shall be recovered by the Vidhan Sabha Secretariat out of the various allowances admissible to him as Member Legislative Assembly.

(4) If a Speaker or Deputy Speaker, as the case may be also ceases to be the Member of Legislative Assembly, before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment, he shall submit a copy of the Challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be a Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereupon, shall be deposited by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance along with interest thereon, the legal heir/heirs of the Speaker/Deputy Speaker or M.L.A., shall regularly deposit the monthly instalments in the Government Treasury and submit the copy of the challan to the Government, every month in token of having deposited the amount.

(7) If the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, or his legal representatives, as the case may be, makes default in the regular payment of instalments either of the principal or interest thereon, or if he becomes insolvent or he fails to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or so much thereof as shall then remain due and unpaid shall become payable forthwith in a lump sum to the Government with interest thereon at the rate prescribed. The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as 'Arrears of Land Revenue'.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered.

7. *Liability to execute mortgage deed securing the payment of the loan.*—In order to secure Government from loss consequent on the demise of the Speaker or the Deputy Speaker,

as the case may be or ceasing to be the Speaker or the Deputy Speaker, before full repayment of the advance and the interest accrued thereon the house so built or purchased, together with the land on which it stands upon, shall be mortgaged to the Himachal Pradesh Government in Form II appended to these rules which shall be executed before the payment of the first instalment, or of lump sum as the case may be, is made and on full payment of the amount which accrues to be due the mortgage shall be released after the execution of the reconveyance deed in Form-III appended to these rules. On the execution of the mortgage deed, the sanctioning authority shall satisfy itself as to the correctness of the applicant's title to the land upon which the house stands or is proposed to be built.

8. *Liability to keep premises in good repairs and insure the premises against fire risks etc.*—The Speaker or the Deputy Speaker shall maintain the house in good repair at his own cost and shall also keep it free from all encumbrances. He shall also have it insured, for a sum not less than the amount of advance sanctioned against fire, flood etc., etc. and furnish an annual certificate to this effect.

9. *Advances given prior to the commencement of these rules.*—Any advance of loan for house building given to the Speaker or the Deputy Speaker as the case may be before the commencement of these rules shall be deemed to have been given under these rules and all the provisions of these rules shall be applicable to such an advance and to its recovery.

FORM I

(See rule 3)

APPLICATION FORM FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

1. Name of the Speaker or the Deputy Speaker (in block letters).....
2. Amount of advance required indicating whether:
 - (i) required for construction of a house; or.....
 - (ii) for the purchase of a built up house.....
3. Place where the house is proposed to be constructed indicating whether it lies within the limits of local body; if so authority sanctioning the plan by the concerned local body may be attached. Detailed plan of the proposed house showing the estimates of total expenditure duly countersigned not below the rank of Assistant Engineer and if the loan is required for the purchase of built-up house, a certificate from the architecture with regard to the reasonableness of the cost of the house be attached
.....
.....
4. Number of instalments in which the advance is proposed to be drawn or in lump-sum
.....
5. Number of instalments including the advance is proposed to be repaid.....
6. Whether the plot on which the Speaker or the Deputy Speaker intends to construct the house is in his proprietorship and possession.....
7. Authentic proof of his title to the plot/land on which the applicant intends to construct the house.....
8. Time by which the Speaker or the Deputy Speaker proposed to undertake the construction of the house and its completion.....

Certified that the above information is correct to the best of my knowledge and that I undertake to mortgage the built up house/the plot on which the house is to be constructed and execute and register a mortgage deed.

Certified that I have not availed of the facility of the advance for the purchase of Motor Car under the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or any other rules.

Dated.....

Encl:.....

.....
(Signature of the Speaker/Deputy Speaker).

FORM II
(See Rule 7)

FORM OF MORTGAGE FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

This INDENTURE made the.....day of.....
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND.....between.....
Shri.....Speaker/Deputy Speaker, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the mortgagor" which term shall where the context so admit include his heirs, executors, administrators and assigns legal representative) of the one part and the GOVERNOR of the Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the mortgagee" which term shall where the context so admits include his successors and assigns) of the other part;

WHEREAS the mortgagor is absolutely seized and possessed of or otherwise well entitled to the land hereditament and premises hereinafter described and expressed to be hereby conveyed, transferred and assured (hereinafter referred to as "the said hereditaments");

AND WHEREAS the mortgagor has applied to the mortgagee for an advance of the sum of Rs.....for the purpose of enabling him to construct his own house/purchase a new built house for his own personal use;

AND WHEREAS under the provision contained in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 (hereinafter referred to as "the said rules" which expression shall where the context so admits include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) the mortgagee has agreed to advance to the mortgagor the said sum of Rs.....payable as follows:—

(a) Rs.....for starting construction.

(b) Rs.....after the house has been completed upto roof level.

(c) or in lump sum.

NOW THIS INDENTURE WITNESSTH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs.....(Rupees.....) paid on or before the execution of these presents to the mortgagor by the mortgagee (the receipt whereof the mortgagor doth hereby acknowledge for the purpose of enabling the mortgagor to defray the hereinbefore recited expenses the mortgagor hereby covenants with the mortgagee to repay to the mortgagee the said sum of Rs.....(Rupees.....) (and such further sum as shall hereafter be paid by him to the mortgagor pursuant to the hereinafter recited agreement in that behalf) and interest thereon calculated, in the manner set forth in the said rules.

AND THIS INDENTURE ALSO WITNESSTH that for the consideration aforesaid the mortgagor doth hereby convey, transfer and assure unto the mortgagee all that piece of land situated in the.....District of.....registration district of.....sub-registration district of.....containing.....more or less now in the occupation of the mortgagor and bounded on the East by.....on the North by.....

on the South by and on the West by together with the dwelling house now erected or hereafter to be erected on the said piece of land together with all rights, easements and appurtenances to the said hereditaments and buildings hereafter erected and built on the said piece of land upto and to the use of the mortgagee absolutely subject to the proviso for redemption hereinafter contained:

PROVIDED ALWAYS if an as soon as the said advance of rupees (and of such further sums as may have been paid as aforesaid) made upon the security of these presents shall have been repaid and interest thereon calculated according to the said rules as in the said rules mentioned or by any other means whatsoever then and in such case the mortgagee will upon the request and at the cost of the mortgagor reconvey retransfer or reassure the said hereditaments until and to the use of the mortgagor or as he may direct and it is hereby agreed and declared that if there shall be any breach by the mortgagor of the covenants on his part herein contained or if he shall die or ceases to be a Speaker/Deputy Speaker before the said sum of rupees (and any further sum as may have been paid as aforesaid) and interest thereon calculated according to the said rules shall have been fully paid off then and in any of such cases it shall be lawful for the mortgagee to sell the said hereditaments or any part thereof either together or in parcels and either by public auction or by private contract with power to nullify or rescind any contract for sale and to resell without being responsible for any loss which may be occasioned thereby;

AND to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sale as the mortgagee shall think fit AND it is hereby declared that the receipt of the mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effectually discharge the purchaser or purchasers therefrom AND it is hereby declared that the mortgagee shall hold the money's to arise from any sale in pursuance of the aforesaid power UPON TRUST in the first place thereout to pay all the expenses incurred on such sale and in the next place to apply such moneys in or towards satisfactions of the moneys for the time being owing on the security of these presents and then to pay the surplus (if any) to the mortgagor AND it is hereby agreed and declared that the said rules shall be deemed and taken to be part of these presents.

The mortgagor hereby covenants with the mortgagee that he the mortgagor will during the continuance of his security observe and perform all the provisions and conditions of the said rules on his part to be observed and performed in respect of these presents and the said hereditaments.

IN WITNESS whereof the mortgagor, hath hereunto set his hand the day and year first above written.

Signed by the said (Mortgagor)

In the presence of

1st witness:

Address

Occupation

2nd witness:

Address:

Occupation

FORM III
(See rule 7)

RECONVEYANCE FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

THIS INDENTURE made the day of 19 ..
BETWEEN THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH (hereinafter called the Government) of the one

part and Shri.....Speaker/Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (hereinafter called "the mortgagor") of the other part is supplemental to an indenture of mortgage, dated the..... day of.....19 , and made BETWEEN the mortgagor of the one part and the Governor of the other part and registered at.....in Book..... Volume....., pages.....to.....and..... as No.....for.....hereinafter called the **PRINCIPAL INDENTURE**.

WHEREAS all moneys due and owing on the security of the **PRINCIPAL INDENTURE** have been fully paid and satisfied and the Governor has accordingly at the request of the mortgagor agree to execute such reconveyance of the mortgaged premises in the within written **INDENTURE** comprised as is hereinafter contained.

NOW THIS **INDENTURE WITNESSTH** that in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises the Governor doth hereby grant, assign and reconvey unto the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns **ALL THAT** piece of land situated in thecontaining.....more or less bounded on the North by.....on the South by..... ON THE East by.....on the West by.....to therewith the dwelling house and out-offices, stables, cook-rooms and out buildings thereon **AND ALL** and singular other than premises in the **PRINCIPAL INDENTURE** comprised or expressed to be thereby assured or which now are by any means vested in the Governor subject to redemption under or by virtue of the **PRINCIPAL INDENTURE** with their rights, easements and appurtenance as in the **PRINCIPAL INDENTURE** expressed and all the astatess right title interest property clean and demand whatsoever of the Governor into out of or upon the same premises by virtue of the **PRINCIPAL INDENTURE** to have and to hold the premises hereinbefore expressed to be hereby, granted, assigned and reconveyed unto and to the use of the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns for ever freed and discharged from all moneys intended to be secured by the **PRINCIPAL INDENTURE** and from all actions, suits, accounts, claims and demands for, or in respect of the said moneys or any part thereof for, or in respect of the **PRINCIPAL INDENTURE** or anything relating to the premises.

AND the Governor hereby covenants with the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns that the Governor has not done or knowingly suffered or been party or privy to anything whereby the said premises or any part thereof are, is or can be impeached, encumbered or affected in title, estate or otherwise how-soever, **IN WITNESS** whereof the parties hereto have hereunto set their hands and seals the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by:

for and on behalf of the Governor of
Himachal Pradesh.
in the presence of.....

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

